

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पारानियर

www.dailypioneer.com



रफेल नडाल ने
21वां ग्रैंडस्लैम
खिताब जीता
स्पोर्ट्स-12

बजट सत्र आज से, उठेगा पेगासस मुद्दा

● जासूसी मामले में ताजा खुलासे को लेकर सरकार से तत्काल स्पष्टीकरण मांगने की रणनीति बना रहा विपक्ष

● कोविड प्रोटोकॉल के तहत सदन संचालन में किए गए कई तरह के बदलाव

दीपक कुमार झा। नई दिल्ली



नई दिल्ली में बैठक करते लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप राष्ट्रपति व राज्य सभा सभापति वैकेया नायडू

शिवसेना, राजद, वाम दल समेत अन्य विपक्षी दल सत्र के पहले ही दिन से दोनों सदनों में पेगासस मामला उठाते हुए सरकार से इस पर तत्काल स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। सदन की बैठक से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी, वहीं उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायडू ने भी पार्टी नेताओं के साथ आभासी बैठक करने वाले हैं। बिड़ला और सोमवार को मुलाकात कर संसद के शीर्ष अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। दोनों पीठासीन अधिकारियों ने आशा व्यक्त की है कि सभी राजनीतिक दल

रचनात्मक रहस में शामिल होंगे और बजट सत्र उत्पादक रहेगा। बिड़ला ने सोमवार दोपहर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी बुलाई है। कोविड महामारी की नई लहर के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों कुल 27 सत्रों में प्रति सत्र एक घंटे कम चलेगी। सत्र के पहले भाग में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा मुख्य कार्य हैं। सत्र के पहले दिन सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे और दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा लोकसभा में 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश

सदस्यों के बैठने के लिए किया जाएगा। बजट सत्र के पहले भाग में 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच 10 बैठकें होंगी, जबकि दूसरे भाग में 14 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 19 बैठकें होंगी। राज्य सभा में सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए शून्यकाल को प्रतिदिन 30 मिनट तक घटाकर 13 घंटे 30 मिनट कर दिया गया है। पहले यह एक घंटे का होता था। सोमवार से शुरू होने वाला बजट सत्र जनवरी 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से आयोजित होने वाला छठा सत्र है। राज्यसभा में 27 बैठकों के दौरान कागजात और रिपोर्ट रखने के अलावा सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए कुल 13 घंटे 30 मिनट के साथ शून्यकाल प्रति दिन 30 मिनट का होगा। प्रश्नकाल का समय 27 घंटे का होगा। सत्र के दौरान छह दिनों में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए कुल 15 घंटे का समय निर्धारित है। सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के दौरान, शुक्रवार को अवकाश होने के कारण गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को गुरुवार को लिया जाएगा। यह ध्यानाकर्षण नोटिस के तहत तत्काल सार्वजनिक चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने और अल्पकालिक चर्चा के रूप में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयकों पर विचार करने और पारित करने के लिए केवल 79 घंटे 30 मिनट का समय बचा है।

किसान संगठन देश में आज मनाएंगे विश्वासघात दिवस

● एसकेएम ने केंद्र सरकार पर लगाया आंदोलन खत्म कराते वक्त किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली



संयुक्त मंच किसानों के समर्थन में 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कृषि मुद्दों पर देश भर में विश्वासघात दिवस मनाने की घोषणा की। एसकेएम के घटक दल के नेता टिकैत ने एक टवीट में कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र को एमएसपी पर अपना किया वादा पूरा करना चाहिए और किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को भी रद्द करना चाहिए।

साल भर विरोध के बाद 9 दिसंबर को सरकार द्वारा दिए गए एक पत्र के आधार पर आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। प्रभावशाली उत्तर भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया कि 9 दिसंबर को सरकार द्वारा किए गए वादों के पत्र के आधार पर दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से अधिक समय से चल रहे किसानों के विरोध को वापस ले लिया गया था, लेकिन वे अधूरे रह गए। दूसरी ओर, एसकेएम ने कहा कि किसान यूपी जाएंगे और लोगों से आगामी

विधानसभा चुनावों में भाजपा को वोट न देने का आग्रह करेंगे क्योंकि वे पिछले साल किसानों से किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। एसकेएम ने कहा कि 31 जनवरी को देश भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। संगठन को उम्मीद है कि यह कार्यक्रम कम से कम 500 जिलों में आयोजित किया जाएगा। बते 9 दिसंबर को किसानों के विरोध के एक साल और 14 दिनों के बाद एसकेएम, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों की सभी लंबित मांगों पर सहमति के बाद प्रदर्शनकारियों ने दिसंबर में दिल्ली की सीमाओं को खाली कर दिया था। इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में घोषणा की थी कि विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा पेश किए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की मुख्य मांगों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। एक साल से अधिक समय से सिंधु, टिकरी और गांधीपुर के प्रमुख सीमा बिंदुओं पर कब्जा करने वाले किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की भी मांग की थी।

चुनाव प्रचार के लिए और ढील मिलने की संभावना

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● चुनाव आयोग प्रचार प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए आज करेगा बैठक

चुनाव आयोग ने बीते 22 जनवरी की बैठक में पांच चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और साइकिल रैलियों पर प्रतिबंध की समीक्षा के लिए सोमवार को आयोग की बैठक होगी। इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग ने देश में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

सूत्रों ने कहा कि राजनीतिक रैलियों, रोड शो, साइकिल और बाइक रैलियों पर प्रतिबंध में छूट राज्यों में मौजूदा कोविड के हालात पर निर्भर करेगा। सूत्रों ने कहा कि आयोग निर्णय लेने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों, मुख्य सचिवों और पांच राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के साथ चर्चा करेगा।

बाजार

सेंसेक्स	57,200
निफ्टी	17,101
सोना	47,777 /10g
चांदी	61,652 /kg

वित्तक न्यूज

मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में एक करोड़ श्रद्धालु कर सकते हैं स्नान: मुख्य सचिव

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रयागराज में चल रहे माघ मेषे का व्रत करने के बाद दीवार चोकर के तीर्थ स्नान को वैध माना है। प्रयागराज में 27 जनवरी को वैश्विक स्तर पर एक करोड़ श्रद्धालुओं के बीच स्नान के आयोजन के लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। प्रयागराज में 27 जनवरी को वैश्विक स्तर पर एक करोड़ श्रद्धालुओं के बीच स्नान के आयोजन के लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। प्रयागराज में 27 जनवरी को वैश्विक स्तर पर एक करोड़ श्रद्धालुओं के बीच स्नान के आयोजन के लिए तैयारियां शुरू की गई हैं।

जैश के शीर्ष कमांडर समेत पांच आतंकी ढेर

भाषा। श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी के तहत पुलवामा और बडगाम जिलों में देर रात हुई दो अलग-अलग मुठभेड़ों में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के एक शीर्ष स्वयंभू कमांडर समेत पांच आतंकीवादियों को ढेर कर दिया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। जेईएम कमांडर जाहिद वानी 2017 से सक्रिय था तथा वह कई हत्याओं और युवाओं को आतंकीवादियों संगठन में भर्ती करने में शामिल था।

पुलवामा में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) कश्मीर, विजय कुमार और सेना के विक्टर फोर्स के जनरल ऑफिसर कर्मांडो-इन-चीफ (जीओसी) मेजर जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने कहा कि आतंकीवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद मुठभेड़ शनिवार को कश्मीर घाटी के पुलवामा और बडगाम जिलों में हुई। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा के नाइरा इलाके में मुठभेड़ में जेईएम के चार आतंकीवादी मारे गए, जबकि एक आतंकीवादी मध्य कश्मीर में बडगाम



मुठभेड़ स्थल पर गोर्वा संगठित सुरक्षा बलों के जवान

जिले के चरार-ए-शीरीफ इलाके में मारा गया, जिसकी पहचान चिल ब्रास खानसाहब निवासी बिलाद अहमद खान के रूप में हुई। कुमार ने संवाददाताओं से कहा, जाहिद वानी जैश का शीर्ष कमांडर था। उसका भाई वान प्लाजा हमले (जम्मू में) में शामिल था और जेल में है। वानी 2017 से सक्रिय था और कई हत्याओं, युवाओं की भर्ती करने में शामिल था। समीर डार की हत्या के बाद जैश-ए-मोहम्मद का जिला कमांडर बना। दरअसल, वह पूरी घाटी का जैश प्रमुख था। यह एक अच्छा अभियान था और मैं सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूँ। आईजीपी ने

राजस्थान में दलित युवक से मारपीट और जबरदस्ती पेशाब पिलायी

भाषा। जयपुर

राजस्थान के चूरू जिले में पुरानी रंजेश के कारण 25 वर्षीय दलित युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने और उसे जबरदस्ती पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रतनगढ़ थाना क्षेत्र के रूखसर गांव निवासी पीड़ित राकेश मेघवाल ने 27 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहता की संबंधित धाराओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने आरोप लगाया कि उमेश जाट ने जाट समुदाय के सात अन्य लोगों राजेश, राकेश, ताराचंद, बीरबल, अक्षय, बिदादीचंद और दिनेश के साथ 26 जनवरी को रात 11 बजे उसे

फेसबुक पोस्ट को लेकर हत्या मामले में मौलाना गिरफ्तार



एटीएस की गिरफ्तार में मौलाना कानगरनी उरमानी (दाएं) और हासिम सागा (बाएं)

● गुजरात के धंधुका में किशन बोलिया की बाइक सवार व्यक्तियों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या

छह जनवरी को सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने

हिंदू महासभा ने मनाया शौर्य दिवस, गोडसे का किया गुणगान

भाषा। मेरठ, ग्वालियर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शनिवार को जहां पूरा देश ने उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की, वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के शारदा रोड स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय में शौर्य दिवस के आयोजन के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। इन लोगों ने गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का गुणगान करते हुए 30 जनवरी का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाया। महासभा ने शांति के दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को दरकिनार कर दिया।

गौरलतब है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हिन्दू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि इस मौके पर कुछ लोगों को नाना आटे नाथूराम गोडसे भारत रत्न दिया गया

है। इसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ निवासी माता महाकाली के परम भक्त महाराज कालीचरण, बंगलुरु निवासी उत्तर भारत के प्रमुख हिंदूवादी नेता शशिकांत शर्मा, लेडी गोडसे के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध डॉ. पूजा शर्मा पांडे, हिंदू डिफेंस के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली निवासी निशांत जंदल, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता, सावरकर टाइम्स के संपादक नई दिल्ली निवासी रामनाथ लुथरा सहित सात लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अशोक शर्मा के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 108 लोगों को यह नाथूराम गोडसे नाना आटे भारत रत्न दिया जाएगा। प्रमुख रूप से भारत के गृह मंत्री अमित शाह, भारत की वित्त मंत्री सीतारमण, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत सहित अन्य लोग इस सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। वहीं हिंदू

लोकतंत्र का गैस चैंबर बना पश्चिम बंगाल : धनखड़

सौरग सेनगुप्ता। कोलकाता

राजभवन और नबना यानी राज्य सचिवालय के बीच जुबानी जंग जारी है। बंगाल के राज्यपाल जनपीत धनखड़ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन पर तगड़ा हमला बोलेते हुए कहा कि राज्य लोकतंत्र का गैस चैंबर बन गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यपाल ने कहा कि बंगाल में मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। राज्यपाल धनखड़ ने यहां तक कहा कि वह इस पवित्र भूमि को खून से लथपथ होते नहीं देख सकते। अब लोग कहने लगे हैं कि यह राज्य लोकतंत्र के गैस चैंबर में बदल रहा है। यह मानवाधिकारों को कुचलने की प्रयोगशाला बन गया है। राज्यपाल ने कहा कि यहां कानून का शासन नहीं, बल्कि शासक का कानून है। उन्होंने कहा कि वह गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। उन्हें अपना कर्तव्य निभाते हुए कई बार अपमानित होना पड़ा है।

देश के 75% से अधिक वयस्कों को लगे दोनों टीके

● खास उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टी देशवासियों को बधाई

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह कोरोना महामारी के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहा है। एक और मील का पत्थर पार करते हुए रविवार तक 75 प्रतिशत से अधिक लोगों को कोरोना की दोनों खुराक लगा दी गई हैं। इस खास उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टवीट कर सभी नागरिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 75 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वह गर्व महसूस कर रहे हैं कि देश में वैक्सिनेशन अभियान बेहद सफल रहा। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा मंत्र सबका साथ



सबका विकास रहा है। रविवार को भारत में 75 प्रतिशत व्यस्क आबादी को टीका लगाया जा चुका है। महामारी के खिलाफ जंग में टीकाकरण एक सफल औजार बना है। उन्होंने यह भी कहा कि टीकाकरण के बाद भी महामारी से निपटने के लिए कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में 62 लाख लोगों को कोरोना की खुराक दी गई। इसके साथ ही कुल 165.7 करोड़ कोरोना की खुराक दी जा चुकी है। हालांकि

देश में कोरोना के 2.34 लाख से अधिक मामले, 893 की मौत

नई दिल्ली (भाषा)। भारत में एक दिन में 2,34,281 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4.10 करोड़ से अधिक हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 893 संक्रमितों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 4,94,091 हो गई। मंत्रालय ने कहा कि देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में 1,19,396 की कमी आई है और अब इनकी तादाद 18,84,937 हो गई है, जो संक्रमितों की कुल संख्या का 4.59 प्रतिशत है। संक्रमण से उबरने की दर 93.89 प्रतिशत है। मंत्रालय के अनुसार देश में दैनिक संक्रमण दर 14.50 प्रतिशत जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 16.40 प्रतिशत रही। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से उबरने वाले लोगों की कुल संख्या 3,87,13,494 हो गई है जबकि कोविड-19 मृत्यु दर 1.20 प्रतिशत है। मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक संक्रमित मिले लोगों की कुल संख्या 4,10,92,522 हो गई है। इस बीच, भारत में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 165.70 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है।

पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट आई है। देश में कुल 2,34,281 मामले सामने आए और 893 लोगों की मौत हुई। वहीं देश में पाँजटिव रेट में कुछ

इजाफा हुआ और संक्रमण दर 14.5 फीसद पहुंच गया। इसके साथ ही सक्रिय मामलों में कुछ गिरावट देखने की मिली। कोरोना से भारत में

अब गुरुग्राम में भी अनाथ बच्चों को गोद ले सकेंगे लोग

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

गुरुग्राम में दत्तक ग्रहण एजेंसी खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। इस एजेंसी के खुलने के बाद अब गुरुग्राम जिलावासियों को बच्चा गोद लेने के लिए किसी अन्य शहर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोमवार को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष पारिशा शर्मा सेक्टर-4 स्थित ओल्ड ऐज होम में गुरुग्राम जिला की इस पहली दत्तक ग्रहण एजेंसी का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगी।

बच्चों के स्वजन का पता न चलने पर व उनको गोद देने की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। जिससे कि बच्चों का लालन-पालन हो सके और निःसंतान दंपतियों को भी संतान सुख की प्राप्ति हो सके। इसके लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें दत्तक ग्रहण एजेंसी का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। उन्होंने कहा कि जिला में उपरोक्त एजेंसी के खुलने से जिलावासियों को अब अनाथ बच्चों को गोद लेने में काफी सहूलियत होगी। जिला के कोई भी दंपति इस दत्तक ग्रहण एजेंसी से निर्धारित नियमों का पालन करते हुए बच्चों को गोद ले सकेंगे।

सीएम ने देर रात तक की नगर निगम व जीएमडीए में छापेमारी

गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी की ली जानकारी

गुरुग्राम में सीसीटीवी के माध्यम से संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखने को कहा

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

एसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी शहर में देर रात तक सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। गुरुग्राम में रात्रि विश्राम के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम गुरुग्राम व गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के कार्यालय में पहुंचे। वहां काफी देर तक वे निरीक्षण करते रहे। मुख्यमंत्री ने रात में शहर में सफाई करने वाली



गुरुग्राम के जीएमडीए कार्यालय में छापेमारी के दौरान सीईओ सुधीर राजपाल से बात करते सीएम मनोहर लाल।

गाड़ियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही कर्मचारियों के बारे में भी पूछताछ की। ड्यूटी रोस्टर भी देखा और अधिकारियों से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री द्वारा देर रात की गई इस छापेमारी के दौरान नगर निगम, जीएमडीए के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। नगर निगम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कंट्रोल रूम में उपस्थित कर्मचारी से पूछा कि इस समय ड्यूटी पर कितने कर्मचारी होने चाहिए। कितनी सफाई मशीन लगी हुई है, उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही

ये कागजात होने पर ही होगी प्रक्रिया शुरू

बच्चे को गोद लेने के इच्छुक परिवार को मौजूदा तस्वीर, बच्चे को गोद लेने वाले का पेन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या कोई ऐसा दस्तावेज जिससे उसकी जन्मतिथि प्रमाणित हो, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन का नवीनतम बिल, उस साल के आय कर की प्रामाणिक कापी, सरकारी चिकित्साधिकारी का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि गोद लेने वाले बच्चे के अभिभावक को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। गोद लेने के इच्छुक दंपती को अपने-अपने मेडिकल प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे। इसके अतिरिक्त शादी का प्रमाण पत्र यदि शादीशुदा हैं तो। व्यक्ति तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण पत्र, गोद लेने के पक्ष में इच्छुक व्यक्ति से जुड़े दो लोगों के बयान आवश्यक हैं।

गोद लेने के लिए रखी हैं कुछ शर्तें
गोद लेने वाले दंपति के लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। दम्पति का शारीरिक, मानसिक, भवनात्मक एवं आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है। उनको

सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है गठित

जिला उपायुक्त डा. यश गर्ग के मुताबिक केंद्र सरकार ने बच्चा गोद लेने के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) गठित की हुई है। संस्था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। बच्चा गोद लेने के लिए कारा की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। कारा मुख्य रूप से बेसहारा छोड़ दिए गए बच्चों को गोद देने का काम करती है।

किसी तरह की गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। जिला बाल कल्याण अधिकारी वॉरेंड यादव ने गोद लेने की

सोमवार को सेक्टर-4 ओल्ड ऐज होम में खोली जाएगी जिला की पहली विशिष्ट दत्तक एजेंसी

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष करेंगी उद्घाटन

शर्तों के बारे में बताया कि अगर संभावित अभिभावक शादीशुदा हैं तो उन दोनों को आपसी सहमति होनी जरूरी है। एक सिंगल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, वहीं एक सिंगल पुरुष सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है।

गीता और रामायण के समान ही हमारा संविधान पवित्र: स्वामी धर्मदेव

भारत में चुनी सरकार का और ऊपर करता का चल रहा है कानून

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गीता और रामायण के समान ही हमारा संविधान अनमोल धरोहर है। पांच दिन पहले पूरे देश में गर्व के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को भी संविधान लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान में सभी भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार की जानकारी देते हुए सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह बात एक माह के कठोर कल्पवास साधना पर बैठे धर्माचार्य, धर्म ग्रंथों और वेदों के मर्मज्ञ महामंडलेश्वर धर्मदेव महाराज ने गांधी पुण्यतिथि के मौके पर कही।



आश्रम हरि मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव को गीता व रामायण सौंपते लोग।

और परम पिता परमेश्वर के विधान की तुलना करते हुए कहा कि प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है की इन दोनों का ईमानदारी के साथ में पालन करते हुए अमल भी किया जाना जरूरी है। जिस प्रकार से हम गीता और रामायण में दी गई शिक्षा और उपदेशों को जीवन में आत्मसात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही भारतीय संविधान को भी प्रत्येक भारतीय को अपना जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार फतह सिंह उजाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। इन्होंने सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को ऐसी नीति भी अवश्य बनानी चाहिए कि देशभर के स्कूलों में संविधान की पुस्तकें अवश्य उपलब्ध करवाई जाए।

अमरूद, आंवला और अनार का बाग लगाने पर दी जा रही है अनुदान राशि

गुरुग्राम। सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने व बागवानी खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। किसान पारंपरिक खेती के स्थान पर बागवानी खेती अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जिला बागवानी अधिकारी पिंकी यादव ने इस विषय में बताया कि सरकार द्वारा किसानों को नए बाग लगाने पर अनुदान राशि प्रदान की जाती है। अमरूद, आंवला व अनार के नए बाग लगाने पर प्रति हेक्टेयर पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। अमरूद के बाग लगाने पर 11 हजार 502 रुपए अनुदान राशि दी जाती है, जबकि अनार के बाग लगाने पर 15 हजार 900 रुपए व आंवला के बाग पर 15 हजार राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। अनुदान

योजना के तहत एक किसान 10 एकड़ तक बाग लगा सकता है। पिंकी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान जमीन के कागजात जैसे कि जमाबंदी व सिजरा आदि के साथ अपनी बैंक कॉपी व आधार कार्ड के साथ जिला बागवानी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

जो किसान बाग लगा चुके हैं वो भी अनुदान के पात्र

पिंकी ने बताया कि किसान किसानों ने एकौकृत बागवानी विकास मिशन के नियमों अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में उपरोक्त फसल के बाग लगाए हैं। जो भी अनुदान राशि के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त किसान नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा सत्यापित नर्सरी के बिल जहां से उन्होंने पौधा खरीदा व उसके साथ साथ नर्सरी की नेमाटोड्स रिपोर्ट भी साथ लेकर आये।

स्वीपिंग मशीन की रिपोर्ट लेकर सीएम दरबार पहुंचे अधिकारी

गुरुग्राम। शनिवार को देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा औचक निरीक्षण के बाद रविवार सुबह नगर निगम के अधिकारी मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की रिपोर्ट लेकर सीएम दरबार में पहुंचे। सीएम ने रात में ही निरीक्षण के दौरान रिपोर्ट सुबह प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे।

रविवार सुबह नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारीगण सफाई व्यवस्था पर रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में पहुंचे। विश्राम गृह में सीएम को लैपटॉप पर दिखाया गया किस प्रकार मैकेनाइज्ड स्वीपिंग सिस्टम काम करता है। इन अधिकारियों ने शनिवार रात को भी सफाई व्यवस्था की रिपोर्ट पेश की। बता दें कि सीएम ने शनिवार देर रात गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में मशीनों से मैकेनाइज्ड स्वीपिंग से सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया था।

दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

पायनियर समाचार सेवा। होडल

शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार बचव एवं सुरक्षा विषय पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य रूप से खंड शिक्षा अधिकारी यशपाल गर्ग ने शिक्षकों को विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ललित कुमार वशिष्ठ भी उपस्थित रहे।



ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेते अध्यापक। कुमार ने कहा सभी अध्यापक 9: 30 से 3:30 तक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक रूप से जुड़े रहे। यह विभागीय आदेश हैं, जिनका हम सभी को पालना करनी चाहिए। उन्होंने कहा जो अध्यापक प्रशिक्षण में नियमित रूप से भाग नहीं लेंगे उनके नाम उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा, साइबर अपराध, कोविड-19, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

पुलिस ने किया नशीला पदार्थ बरामद, तीन शान्तिरों को किया गिरफ्तार

कैलाश मंगला। होडल

होडल सीआइए पुलिस ने नेशनल हाइवे डबचिक मोड़ पर घेराबंदी कर एक गाड़ी से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजे के साथ तीन युवकों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है।



नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी सीआइए की गिरफ्तार में।

ले लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपने नाम बेरया मोहल्ला गांव सिगांर निवासी ललित, अरवि कालोनी गुरुना मेवात निवासी युसुफ गुंवा झारोखड़ी निवासी मुफ्फिद बताया। पुलिस को युवकों के पास से 52 किलो 360 ग्राम गांजा बरामद किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार दिनेश कुमार की

अग्रवाल वैश्य समाज की युवा इकाई की हुई घोषणा

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने संगठन की युवा इकाई की घोषणा करते हुए नवदीप बंसल डबवाली को पुनः प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। समाज के प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिमांशु हिंदुस्तानी ने बताया कि नवगठित इस 10 सदस्यीय युवा इकाई में नवदीप बंसल के साथ हिमांशु गोयल जटलाना, यमुनानगर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अधिवक्ता नीतिग्र अग्रवाल रेवाड़ी को उपाध्यक्ष, वेदप्रकाश गर्ग कैथल व रवि गर्ग बधवानिया चरखी दादरी को महासचिव बनाया गया है। इसी क्रम में हिमांशु गोयल कैथल व विनय जैन नारनौल को सचिव नियुक्त किया गया है। शुभम अग्रवाल जफरपुर अम्बाला व राहुल गुप्ता रोहतक को संगठन सचिव तथा अधिवक्ता ऋषभ जैन गुरुग्राम को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी ने बताया कि शेष कार्यकारिणी का गठन भी शीघ्र ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्रवाल वैश्य समाज युवाओं के समग्र विकास के लिए निरन्तर

गुरुग्राम के ऋषभ जैन को बनारा गया है प्रवक्ता

प्रयासरत है क्योंकि जब भी बदलाव आता है तो युवा ही लेकर आते हैं। सुमित हिन्दुस्तानी ने कहा कि वतजमान परिदृश्य में किसी भी समाज का विकास उसकी राजनीति भागीदारी पर निर्भर कर रहा है। समाज के युवाओं के राजनीति में आने से ही उपेक्षित वैश्य समाज को सही नेतृत्व मिलेगा। अपनी नियुक्ति पर युवा प्रदेश अध्यक्ष नवदीप बंसल ने अपनी कार्यकारिणी की ओर से समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला व अन्य पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जो भरोसा व विश्वास उन पर जताया गया है, उस पर खरा उतरते हुए जल्द ही संगठन की विस्तारसभा एवं लोकसभा इकाईयों का गठन किया जाएगा। नवदीप बंसल ने कहा कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में नवनीयुक्त सभी पदाधिकारियों का पुष्कर, राउतस्थान में एक प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा।

लेंसकार्ट ने गणतंत्र दिवस पर 73 स्टोर लॉन्च किए, देश में सबसे बड़ा रिटेल विस्तार

लेंसकार्ट की इस साल पूरे भारत में 400 और स्टोर स्थापित करने की योजना, फरवरी 2022 में खुलेगा 1000वां आउटलेट

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारत के सबसे तेजी से बढ़ते ओमनी-चैनल आई-वियर ब्रांड लेंसकार्ट ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के 46 शहरों और 19 राज्यों में कुल 73 स्टोर लॉन्च किए। लेंसकार्ट का लक्ष्य वित्त वर्ष 2022 में कुल 400 स्टोर स्थापित करना है। लॉन्च किए गए 73 स्टोर में 10 ऑनलाइन स्टोर, कर्नाटक में 6-6 स्टोर शामिल थे। इसके साथ ही कर्नाटक ने अगले महीने फरवरी में अपना 1000वां स्टोर स्थापित करने की काउंटडाउन शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस पर शुरू किये गए 73 स्टोर लॉन्च में बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्य भी शामिल हैं।

संक्षिप्त समाचार

स्वास्थ्य शिविर में तीन सौ लोगों ने कराई जांच



सोहना के गांव जखोपुर में लगे स्वास्थ्य शिविर में जांच कराते हुए नागरिक। सोहना नगर परिषद वार्ड-9 के गांव जखोपुर में समासेवी महिला ने पुत्र के जन्मदिन पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर में करीब 300 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। रविवार को शहर के वार्ड-9 के गांव जखोपुर में लगे स्वास्थ्य शिविर में करीब तीन सौ लोगों की शारीरिक जांच की गई। शिविर का आयोजन समाजसेवी ऊषा शरण ने किया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा यह छठवां शिविर लगाया है। लेकिन बेटे कार्तिक के जन्मदिन पर इसका आयोजन किया गया है। जरूरतमंदों को शिविर में दवाइयां फ्री दी गई। ऊषा शरण ने बताया कि समाज सेवा के तरीके अनेक होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अच्छा खानपान न होने के कारण बीमारियों ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है।

अवैध हथियार समेत बदमाश गिरफ्तार

सोहना। अपराध शाखा पांच पुलिस ने बदमाश को अवैध हथियार समेत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ सिटी थाना में मामला दर्ज कराया गया है। जिला नूह थाना तावडू के गांव चिल्ला निवासी फरमान उर्फ मल्लू को शहर के तिकोना पार्क के पास गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस को जेब से अवैध हथियार मिला है।

अरावली पहाड़ी बना अवैध शराब का अड्डा, शराब बरामद

सोहना। भोंडसी थाना पुलिस ने रायसीना से लगती अरावली पहाड़ी के फार्म हाउस में चलाए जा रहे अवैध शराब के ठेका पर छापेमारी की। मौके से पुलिस ने शराब की पेटियां बरामद की हैं। तलाशी के दौरान 20 पेटियों में भरी 480 बीयर की बोतल और नौ पेटियों से 108 बोतल शराब की पायी गई हैं। शनिवार को भोंडसी थाना पुलिस को शराब के दौरान सूचना मिली कि अरावली के अंसल क्षेत्र के ए33 फार्म में अवैध रूप से शराब का ठेका चल रहा है। जिसे इन्दापुरम गाजियाबाद निवासी विशेष पुत्र सुभाष चला रहा है। विशेष अंसल में रहने वाले चौकीदार, मजदूर, दुकानदार और आसपास के ग्रामीणों को बचता है। पुलिस ने फार्म हाउस में छापेमारी करते हुए बीयर की 20 पेटि और अलग-अलग श्रेणी की नौ पेटि अवैध शराब को पकड़ी हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ उसके खिलाफ अवैध शराब बेचने का मामला दर्ज किया है।

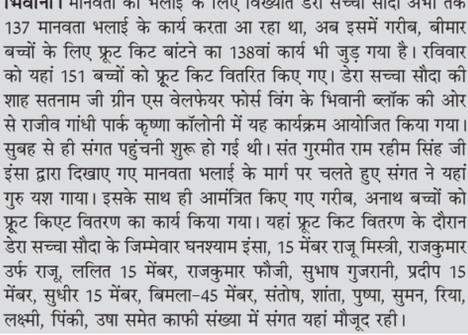
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

होडल। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वें पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया। जिसमें परिषद के सदस्यों ने गडिया बाजार स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उषे श्रद्धांजलि दी। अध्यक्षता परिषद के प्रांतीय संयोजक डॉ. जेके मिश्र ने की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर डॉ. जेके मिश्र ने कहा कि महात्मा गांधी अहिंसा के पूजारी थे। उन्होंने कहा कि हमें उनके बताए गए कदमों पर चलकर अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। गांधी जी शान्ति, सत्य, अहिंसा का पालन करने वाले रवैए के कारण ही लोग उन्हें महात्मा से संबोधित करने लगे थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी 1916 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और फिर हमारे देश की आजादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। इस मौके पर डॉ. राजेश जैन, नवीन मंगला, कमल खन्ना, रिषी बंसल, मुरारी लाल गोला, चंद्रप्रकाश जैन, श्याम सुन्दर मंगला के अलावा परिषद के अन्य सदस्य मौजूद थे।

डेरा सेवादलों ने 151 बच्चों को दिए फूट्स

भिवानी। मानवता की भलाई के लिए विख्यात डेरा सच्चा सौदा अभी तक 137 मानवता भलाई के कार्य करता आ रहा था, अब इसमें गरीब, बीमार बच्चों के लिए फूट किक वांटने का 138वां कार्य भी जुड़ गया है। रविवार को यहां 151 बच्चों को फूट किक वितरित किए गए। डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीन एसे वेल्फेयर फोर्स विंग के भिवानी ब्लॉक की ओर से राजीव गांधी पार्क कृष्णा कॉलोनी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से ही संगत पहुंचनी शुरू हो गई थी। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ईसा द्वारा दिखाए गए मानवता भलाई के मार्ग पर चलते हुए संगत ने यहां गुरु यश गया। इसके साथ ही आमंत्रित किए गए गरीब, अनाथ बच्चों को फूट किक वितरण का कार्य किया गया। यहां फूट किक वितरण के दौरान डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेवार घनश्याम ईसा, 15 मंबर राजू मिस्त्री, राजकुमार उर्फ राजू, ललित 15 मंबर, राजकुमार फौजी, सुभाष गुजरानी, प्रदीप 15 मंबर, सुधीर 15 मंबर, बिमला-45 मंबर, संतोष, शांता, पुष्पा, सुमन, रिया, लक्ष्मी, पिंकी, उषा समेत काफी संख्या में संगत यहां मौजूद रही।

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करते हुए।



महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करते हुए।

बंद स्कूल प्रभावित शिक्षा

अभी किसी क्षेत्र को यह स्पष्ट नहीं है कि स्कूल पुनः खोलना ठीक होगा या नहीं। उम्मीद थी कि भारतीय साई-कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम-इस्काका या राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स या महामारीविज्ञानियों व वायरसविज्ञानियों की संस्था कम से कम अब स्कूल पुनः खोलने के मामले में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। स्कूल लगभग पूरे 2020 व अधिकांश 2021 वर्ष में बंद रहे हैं। कुछ राज्यों में दूसरी लहर के बाद वे खुलना शुरू हुए, पर ओमीक्रॉन सामने आने के बाद फिर बंद हो गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान लहर तेजी से घट रही है, पर वे हमें यह नहीं बताना चाहते हैं कि क्या बच्चों का स्कूल लौटना सुरक्षित है। हालांकि, नियंत्रण हटाए जा रहे हैं, पर कोई राज्य सरकार स्कूल पुनः खोलने का फैसला लेने को तैयार नहीं है। क्या ऐसा कुछ है जिसे हम नहीं जानते, पर जानना चाहते हैं? अथवा कोई यह नहीं जानना चाहता है क्योंकि कोई यह जोखिम नहीं उठाना चाहता है कि स्कूल पुनः खोलने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा या नहीं? बच्चों और उनके माता-पिता को इस बारे में स्पष्टीकरण चाहिए। 600 से अधिक दिनों से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको कक्षाओं में अध्ययन से दूर रखा गया है तथा जबरन घरों में एकांतवास के लिए मजबूर किया गया है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। इससे वे मानसिक परेशानियों के शिकार हो गए हैं। हम आमतौर से वैज्ञानिकों से सुनते हैं कि बच्चों का प्रतिक्षण तंत्र मजबूत होता है जो उनकी आसानी से संक्रमित होने से बचाता है। इसके उलट महीनों तक घर पर अलग-थलग रहने या शारीरिक गतिविधि के अभाव में उनकी प्रतिरक्षा क्षमता घटी है।



इस बारे में कोई डेटा नहीं है कि बच्चे कैसे संक्रमण का सामना करते हैं या इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं है कि स्कूलों में कठोरतम सावधानियों से बच्चों के टीकाकृत होने तक संक्रमण से बचा जा सकता है। बड़ी सीमा तक स्कूल पुनः खोलने के बारे में सरकार की झिझक समझी जा सकती है, क्योंकि बच्चे आज जनसंख्या का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिनके लिए वैक्सिन नहीं है। अब 15 वर्ष से अधिक आयु वालों को टीके की पहली खुराक दी जा रही है। दो साल से बड़े बच्चों के लिए वैक्सिनों की अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। संभवतः गर्मी की शुरुआत तक यही स्थिति बनी रहेगी जब उनको पांच वैक्सिनें उपलब्ध होंगी। इनमें कैडिला हेल्थकेयर की जायकोव-डी, भारत बायोटेक की कोवैक्सिन, सीएम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स, बायोलाजिकल ई की आरबीडी तथा जॉन्सन एंड जॉन्सन की 26कोवैक्स वैक्सिन शामिल हैं। इस बीच बच्चों में शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने के मामले में गिरावट का राष्ट्रीय आंकलन होना चाहिए तथा उसके संभावित मानक निर्धारित होने चाहिए। शिक्षा के आनलाइन तरीके के बारे में कमियों के बारे में सभी जानते हैं। गरीब परिवारों के बच्चे डिजिटल उपकरण न होने या उनको चलाने के लिए बिजली की उपलब्धता में कमी का शिकार हैं। माता-पिता ने यह पूछना शुरू कर दिया है कि आखिरकार शिक्षा को अर्थव्यवस्था की तरह 'आवश्यक' सेवा क्यों नहीं माना जा रहा है। उनको आश्चर्य होता है कि बार सबसे पहले खुलते हैं, पर स्कूल नहीं। उनका कहना है कि यह समझना नौसिखियापान है कि जब परिवार के लोग नियमित रूप से काम पर जा रहे हों तो बच्चे कैसे वायस से बचेंगे। समय आ गया है कि स्कूल पुनः खोलने के बारे में निर्णय करते समय भावनाओं के बजाय तार्किकता से काम लिया जाए। कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कि स्कूलों को बंद रखा जाए।

भाजपा की मददगार मोदी-कैप्टन जोड़ी

अनेक विधानसभा चुनावों में अकेले मोदी भाजपा का चेहरा रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए अतिरिक्त व्यक्तित्व या मुद्दे की भी जरूरत हो सकती है।



अमिताभ शुक्ल
(लेखक दि पार्ययन चंडीगढ़ के स्थानीय संपादक हैं)

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के घरों और बिजनेस परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़े। यह उस प्रवृत्ति के अनुसार है, जिसका पालन केन्द्रीय एजेंसियां चुनाव वाले राज्यों में करती हैं। पंजाब के एक नेता ने इन छापों के समय पर सवाल उठाते हुए कहा, 'इससे काफी धुंआ सा उठता है, यह धुंआ काफी समय तक दिखता है, लेकिन इसका लक्षित लोगों की चुनाव संभावनाओं पर बहुत कम अथवा लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।' उनका कहना है कि चुनावों की अधिधोषणा जारी होने तथा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद इन छापों का क्या औचित्य है। राजनीति में गहराई तक जमे लोग जानते हैं कि ईडी या आयकर छापों या किसी अन्य केन्द्रीय एजेंसी के छापे से भाजपा को चुनावों में कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि प्रभावित लोगों द्वारा छापे के अगले दिन स्वयं को पीड़ित बताने के कारण इनकी आग बुझ जाती है। एजेंसियों द्वारा बरामदगी का हिसाब देने के अगले तीन-चार दिनों में धुंआ भी साफ हो जाता है और एक सप्ताह में सारी धूल बैठ जाती है। इस प्रकार पंजाब में भाजपा को पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा दो बार मुख्यमंत्री रह चुके अमरिंदर सिंह की राजनीतिक क्षमता पर निर्भर रहना होगा जिसका कुल मिला कर राज्य के सर्वोच्च पद पर साढ़े नौ साल का कार्यकाल रहा है। जैसा कि हम अब तक समझ गए हैं, राष्ट्रपति प्रणाली जैसे चुनाव होने पर मोदी का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जहां उनके कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं और वे आसानी से दूसरों के बीच सर्वोच्च शिखर पर होते हैं। 2014 व 2019 में यही हुआ जब स्पष्ट पद से मोदी बनाम अन्य का सवाल पैदा हुआ। मुसकावला नहीं कर सके तथा परिणामों में किसी को आश्चर्यचकित नहीं किया। इस मोर्चे पर 2022 में भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।

लेकिन इसके साथ ही कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में स्पष्ट हो गया है कि केवल मोदी ही भाजपा का चेहरा नहीं हो सकते हैं और उनको विजय के लिए किसी



अतिरिक्त चीज, अतिरिक्त व्यक्तित्व या अतिरिक्त मुद्दे की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस ने इस तथ्य के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया है कि मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसी राज्य से आते हैं। देश भर के राज्यों में अनेक ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्थानीय व क्षेत्रीय नेता अपने गृह क्षेत्रों में असर बनाए रखते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में एकमात्र मोदी ही भाजपा का चेहरा थे, लेकिन पार्टी इस तथ्य के बावजूद बहुत नहीं प्राप्त कर सकी कि वह पांच वर्ष से इस स्थानीय संस्था पर शासन कर रही थी। यह अलग बात है कि राजनीतिक पैतरेबाजी के चलते वह 'अल्पसंख्यक' मेयर बनवाने में सफल रही, जबकि सदन में भाजपा की तुलना में आम आदमी पार्टी को दो सीटें अधिक थीं।

इस प्रकार पंजाब में मतदान प्रक्रिया और उसके परिणाम पर मोदी का ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, भले ही उनके समर्थक चाहे जो कहें। चुनाव के पहले वे फिरोजपुर में घोषित रैली को संबोधित करने वाले थे, पर उसे बहु-प्रचारित सुरक्षा खामी के चलते रद्द करना पड़ा। हालांकि, उस दिन मौसम खराब था जिसने लोगों को बाहर निकलने के लिए मजबूर किया, लेकिन रैली स्थल पर तीन कृषि कानून वापस लेने के बावजूद कम भीड़ से स्पष्ट होता है कि भाजपा को अभी पंजाबियों का विश्वास प्राप्त करने के लिए कई अन्य पुल पर करने होंगे। यह कमी पूरी करने के लिए एक चुनाव का

चुनाव में शिअद या भाजपा एक-दूसरे पर हमले नहीं कर रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि दोनों के बीच ज्यादा मतभेद नहीं हैं। यदि भाजपा विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो वह 2024 के लोकसभा चुनाव में शिअद से बहुत ज्यादा सीटें मांगने में सफल होगी। अनेक भाजपा नेता यही सोचते हैं क्योंकि वयोवृद्ध कैप्टन अमरिंदर राज्य में भावी राजनीतिक योजनाओं की कोई गारंटी नहीं दे सकते।

समय बहुत कम है। इसमें काफी समय लगेगा और इसके लिए भाजपा को लगातार प्रयास करते हुए सही फर्मुले के साथ पंजाब में स्थानीय सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का

सवाल है, राज्य में बहुत से लोगों का विश्वास है कि पंजाब लोक कांग्रेस बनाने और भाजपा के साथ गठजोड़ करना सत्ता में पहुंचने का सुनिश्चित रास्ता नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि उनको अपमानित करने वाली कांग्रेस चुनाव में पराजित हो। यह मानने वालों में कुछ अमरिंदर-समर्थक भी हैं। पुरानी पार्टी के बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि संभावित त्रिंशुक्त सदन में लगभग आधा दर्जन विधायकों के साथ अमरिंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चुनाव के बाद की संभावनाओं के किंतु-परंतु पर विचार करने के बजाय यह स्पष्ट है कि भाजपा राज्य के सिख समुदाय में अपना असर बढ़ाने के रोडमैप पर निकट भविष्य में काम करेगी।

इस सीमांत राज्य में उसका शिरोमणि अकाली दल के साथ दो दशक से अधिक समय तक गठबंधन रहा है और जूनियर पार्टनर के रूप में वह शहरी क्षेत्रों की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी। दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे की कमी पूरी की है, जहां भाजपा एक ऐसे राज्य में हिंदू दृष्टिकोण पेश करती थी जो 1980 के दशक तथा 1990 के दशक में चरमपंथ से अत्यधिक प्रभावित था। अब तीन कृषि कानून वापस लेने के बाद राज्य में राजनीतिक स्थितियां बदली हैं। कानूनों की अवधारणा बनने और अंततः इनके पास होने के बाद भाजपा या शिरोमणि अकाली दल-शिअद में से किसी को अनुमान नहीं था कि राज्य में इसके क्या

परिणाम होंगे। राज्य के सिख किसानों के दिल्ली सीमाओं पर एकत्र होने तथा दशकों में सर्वाधिक प्रभावी अहिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद कृषि कानूनों का विरोध पंजाब में एक प्रकार का जानाबूझ बना गया। ऐसे में कोई भी पार्टी इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता। शिअद ने पहल करते हुए साझीदार भाजपा से अलग रास्ता अपनाया और उसकी प्रतिनिधि हरसिमरत कौर बाल्ल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

जब भाजपा का शिअद से गठबंधन था, तब भी खासतौर से 2007 से 2017 के बीच दस साल के शासनकाल में भाजपा के भीतर से मांगें उठ रही थीं कि उसे स्वतंत्र रूप से चुनाव में जाना चाहिए। 2014 में मोदी के सर्वोच्च नेता बनने, कई राज्य चुनावों में भाजपा की विजय तथा देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के बाद ये स्वर और तेज हो गए। इस प्रकार दशकों में पहली बार 2022 में भाजपा बड़े भाई के साथ गठबंधन के बजाय कांग्रेस छोड़ने वाले पीएलसी प्रमुख अमरिंदर सिंह के साथ लगभग 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यदि भाजपा अच्छे प्रदर्शन करती है और एक नेता से दूसरे नेता के बीच अच्छे प्रदर्शन के मानक बदलते हैं तो पंजाब में नए ध्रुवीकरण की संभावना है। लेकिन यह भी तथ्य है कि अनेक कारणों से भाजपा ग्रामीण पंजाब में आगे बढ़ने में विफल रही है, ऐसे में इस पार्टी को लंबे संघर्ष व परिवर्तन की जरूरत है। शिअद के अनेक नेताओं का विश्वास है कि अमरिंदर सिंह की पीएलसी केवल चुनावी संरचना है और इसमें व भाजपा में कोई अंतर नहीं है अथवा यह बहुत कम है। इसका कारण यह है कि कृषि कानूनों पर मतभेद का अब कोई स्थान नहीं है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए शिअद का भाजपा से फिर गठबंधन हो जाए तथा 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच परोक्ष समझदारी विकसित हो।

वैसे भी चुनाव में शिअद या भाजपा एक-दूसरे पर हमले नहीं कर रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि दोनों के बीच ज्यादा मतभेद नहीं हैं। यदि भाजपा विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो वह 2024 के लोकसभा चुनाव में शिअद से बहुत ज्यादा सीटें मांगने में सफल होगी। अनेक भाजपा नेता यही सोचते हैं क्योंकि वयोवृद्ध कैप्टन अमरिंदर राज्य में भावी राजनीतिक योजनाओं की कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं तथा शिअद वह हिंदू-सिख तस्वीर पूरी करती है जिसे भाजपा को बाकी देश में भी सहायता पहुंचाई है।

सावरेन बांड का स्वागतयोग्य विचार

विदेशी मुद्रा प्रवाह से एक सीमा तक बांड लाभदायक सिद्ध होंगे पर क्रियान्वयन के बाद इस दिशा में सावधानी से आगे बढ़ना होगा।



शशांक सौरव
(लेखक नीति विश्लेषक हैं)

केंद्रीय बजट 2022 आने वाला है। अनुमान है कि भारत के सावरेन बांड को वैश्विक बांड सूचकांक में शामिल किया जाएगा। कुछ समय पहले आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि यह प्रक्रिया जारी है और कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी। ऐतिहासिक रूप से भारत देश के कर्ज के विदेशी स्वामित्व के विचार के खिलाफ रहा है। यह नीतिगत पसंद मुख्यतः 1990 के दशक में हमारी भुगतान संतुलन के अनुभव के कारण है। सरकार ने कार्पोरेट क्षेत्र को विदेशी पूंजी के लिए एफडीआई-एफआईआई माध्यम करना था। फेरलू तत्वों की मिलीभगत से शुरू किए गए इस भारत विरोधी अभियान ने देश की अहिंसक छवि को कट्टरपंथी कथन से बदलने की कोशिश की। रिपोर्टों के अनुसार, इस कैपेन में बहिष्कार, डिसइंवेस्टमेंट जैसी तरकीबें अपनाई गईं, जिनका प्रभाव विवादास्पद था। पिछले कुछ वर्षों में भारत विरोधी कुछ कहानियां गड़ी गईं हैं। ये सब

का सावरेन बांड के प्रति कठोर दृष्टिकोण रहा है। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अचानक पूंजी प्रवाह की अल्पकालीन स्थितियों से निपटने में सक्षम है। कोविड महामारी ने एक ओर राजस्व सृजन घटाया है, वहीं सार्वजनिक खर्च बढ़ा है। सरकार ने गैर-कर राजस्व जैसे विनिवेश प्रक्रियाओं तथा परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण तरीके अपना कर लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया है, पर वह ज्यादा सफल नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा जारी बांडों की आय जनवरी, 2022 में 6.54 प्रतिशत पहुंच गई थी जो दो साल में सर्वाधिक है। लेकिन आर्थिक प्रगति अभी महामारी की छाया में है और सरकार द्वारा उधार लेने में ज्यादा कमी आने की संभावना नहीं है।

जब अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो जाएगी और कर्ज की मांग बढ़ेगी तब बैंकों को सरकारी कागजों की ज्यादा आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसा लगता है कि जल्द ही यह स्थिति आने वाली है। इसका अर्थ ब्याज भुगतान पर ज्यादा पैसा



निकलना तथा सरकार के पास ढांचगत खर्च व परिसंपत्ति सृजन के लिए कम पैसा बचना होगा। विदेशी पूंजी प्रवाह से एक सीमा तक बांडों से होने वाली आय में कमी हो सकती है। लेकिन इस प्रवाह से आईएनआर बढ़ेगा जिससे निर्यातकों

को नुकसान संभव है। ऐसे में विनियम दर का आरबीआई द्वारा प्रबंधन बाजार हस्तक्षेप नीतियों के साथ जारी रहेगा। सरकार द्वारा दी गई विभिन्न रियायतों और प्रोत्साहनों के बावजूद निजी निवेश नहीं बढ़ रहा है और सरकार को लगभग सभी

बड़ी ढांचगत परियोजनाओं में निवेश के लिए आगे आना पड़ रहा है। फेरलू कर्ज का सीधा प्रभाव तरलता पर पड़ता है जिससे मांग-उपभोग व मुद्रास्फीति सीधे प्रभावित होते हैं। हमारे मामले में विदेशी कर्ज का प्रयोग प्रगति के लिए ही किया जाना चाहिए तथा विदेशी पूंजी को देश के राजकोषीय घाटे के प्रबंधन में नहीं होना चाहिए। देश के जोखिम का दृष्टिकोण खरीदारों द्वारा सरकारी कागजों की आवश्यकता प्रदर्शित करता है। आमतौर से क्रेडिट डिफ्ल्ट स्वैप का प्रयोग कर्जदारों द्वारा जारी सिक्युरिटीज के मूल्यांकन में होता है। भारत की पंचवर्षीय सीडीएस सावरेन कोविड-संबंधी अनिश्चितता के कारण मार्च 20 में शिखर पर पहुंचने के बाद लगातार गिरी हैं। इसका अर्थ है कि कर्ज के बारे में दृष्टिकोण में सुधार हुआ है। भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग स्थिर बनी हुई है और मूडी द्वारा जून 2020 में इसे बीएएए2 से गिरा कर बीएए3 करने की भारी आलोचना हुई थी।

भारतीय बांडों पर आकर्षक लाभ के कारण विदेशी निवेशकों को लाभ होता है। यदि विनियम दर पर ध्यान दिया जाए तो इन सिक्युरिटीज की मांग पर कोई सवाल नहीं उठता है। आरबीआई को कुछ क्षेत्रों के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा आरबीआई और वित्त मंत्रालय को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। हालांकि, कुल सीमा 6 प्रतिशत है तथा भारत को विदेशी पूंजी की मांग पर टैक्स का दृष्टिकोण प्रतिकूल प्रभावित करता है। निश्चित अंतराल पर ब्याज प्राप्ति तथा पूंजीगत लाभ पर टैक्स का महत्वपूर्ण आयाम है। ऐसे में विदेशी निवेशकों को दी गई कोई रियायत फेरलू निवेशकों के लिए हानिकारक हो सकती है। विदेशी निवेशकों को रियायत तथा फेरलू निवेशकों को लेनदेन पर टैक्स समता सिद्धान्त के खिलाफ होगा। इस मामले में ढांचगत परिवर्तन सोच में बदलाव का संकेत देता है। यह स्वागत योग्य कदम है, पर क्रियान्वयन के बाद इस दिशा में सावधानी से आगे बढ़ना होगा।

अप की बात

छवि बिगाड़ने की साजिश

मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के अंतरराष्ट्रीय इस्लामी संगठन ने भारत की छवि खराब करने के लिए पिछले साल सितंबर में बहिष्कार अभियान चलाया था। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इस अभियान का मकसद देश की प्रमुख हरितियों को बंद करना था। फेरलू तत्वों की मिलीभगत से शुरू किए गए इस भारत विरोधी अभियान ने देश की अहिंसक छवि को कट्टरपंथी कथन से बदलने की कोशिश की। रिपोर्टों के अनुसार, इस कैपेन में बहिष्कार, डिसइंवेस्टमेंट जैसी तरकीबें अपनाई गईं, जिनका प्रभाव विवादास्पद था। पिछले कुछ वर्षों में भारत विरोधी कुछ कहानियां गड़ी गईं हैं। ये सब

सकारात्मक हो सदन की बहस

विधानसभा, संसद और अन्य सदन में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कब सुधरेगा? यह गंभीर सवाल है। उनके अनियंत्रित व्यवहार को रोकने के लिए सख्त नियमों को लागू करने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि सदन में अभद्र व्यवहार करते हैं तो उनपर कौनसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? इस बारे में नए कानून अलाग करना चाहिए। अगर, बारीकी से देखें तो पता चलता है कि कहीं न कहीं यह भी राजनीतिक दलों के पक्ष अथवा उन्हीं से प्रभावित होकर काम करते हैं फिर चाहे वो इन विभागों में नियुक्ति का मामला हो या प्रमोशन व ट्रांसफर का, दोनों में सत्ता की महत्ता देखने को मिलती है। देशभर में ओमीक्रॉन के नित नए मामले आ रहे, पुलिस प्रशासन आम जनता को सतर्क कर रही, व्यापारियों को मास्क न लगाने पर मुकदमा की बात कर रही, बड़े बड़े बैंकर पोस्टर और मोबाइल के काल्ट द्युन भी आगाह कर रहे, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का क्या फर्क पड़ने वाला। चुनाव आयोग ने डिजिटल और डोर टू डोर कैम्पेन की अनुमति तो दे दी, लेकिन लगातार डोर टू डोर दौरे से, सुरक्षा और भीड़ में बिना मास्क लगाए लोगों से संक्रमण का खतरा नहीं होगा। हमें खुद सोचने की आवश्यकता है।

— अमन जायसवाल, दिल्ली विवि

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

चुनाव आयोग की बारी

भारत में स्वतंत्र रूप से कार्यरत संस्थान पर सवाल उठाना, खतरों से खाली नहीं होता। फिर चाहे वो न्यायपालिका हो या चुनाव आयोग, दोनों की अलग पहचान है। अगर, बारीकी से देखें तो पता चलता है कि कहीं न कहीं यह भी राजनीतिक दलों के पक्ष अथवा उन्हीं से प्रभावित होकर काम करते हैं फिर चाहे वो इन विभागों में नियुक्ति का मामला हो या प्रमोशन व ट्रांसफर का, दोनों में सत्ता की महत्ता देखने को मिलती है। देशभर में ओमीक्रॉन के नित नए मामले आ रहे, पुलिस प्रशासन आम जनता को सतर्क कर रही, व्यापारियों को मास्क न लगाने पर मुकदमा की बात कर रही, बड़े बड़े बैंकर पोस्टर और मोबाइल के काल्ट द्युन भी आगाह कर रहे, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का क्या फर्क पड़ने वाला। चुनाव आयोग ने डिजिटल और डोर टू डोर कैम्पेन की अनुमति तो दे दी, लेकिन लगातार डोर टू डोर दौरे से, सुरक्षा और भीड़ में बिना मास्क लगाए लोगों से संक्रमण का खतरा नहीं होगा। हमें खुद सोचने की आवश्यकता है।

— अमन जायसवाल, दिल्ली विवि

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

फरमाया

समाजवादी पार्टी की लाल टोपी मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ितों और अयोध्या में मारे गए कारसेवकों के खून में रंगी हुई है।

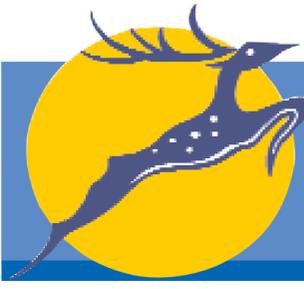
— योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

त्रिपक्षीय महा विकास अघाड़ी (एमवीए) महाराष्ट्र का राजनीतिक भविष्य है और शिवसेना-भाजपा के पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है।

— संजय राउत
शिवसेना नेता

भाजपा शतक बनाने से एक अंक कम है। उन्होंने अब तक 99 अपराधियों को टिकट दिए हैं।

— अखिलेश यादव
सपा प्रमुख



पायनियर उत्तर प्रदेश चुनाव



चौपाल

बसपा को अब पुराने चेहरों पर यकीन नहीं

● 109 में सिर्फ चार को मिला दोबारा अवसर

● सिटिंग सीट में सिर्फ मांट से श्याम सुंदर शर्मा मैदान में

सतीश सिंह | लखनऊ

यूपी विधानसभा की तैयारियों में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार जमीनी स्तर पर मिशन फतेह को लेकर ऐसी समीक्षा की कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार पार्टी के 97 फीसद चेहरे मैदान से गायब हो गए। पहले और दूसरे चरण की कुल 109 सीटों में सिर्फ मथुरा की मांट सीट से विधायक श्याम सुंदर शर्मा ही मैदान में हैं। वहीं 2017 के चुनाव में रामपुर मनिहारन सीट से रनर रहे रविन्द्र कुमार मोह्लू और धामपुर सीट से मोहम्मद गाजी और गोवर्धन सीट से राजकुमार रावत को 2022 के चुनाव में पार्टी ने दोबारा मौका दिया है।

वर्ष 2007 के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते सरकार बनाने वाली बसपा इस चुनाव के बाद से ही लगातार हाशिये की तरफ बढ़ रही है। अब इसके पीछे कारण चाहे पार्टी छोड़ कर जाने वाले नेताओं की लंबी फेहरिस्त हो या फिर आम जनमानस के बीच व्याप्त भ्रांतियां, इसके बारे में पार्टी ही बखूबी बता सकती है। लेकिन चुनाव से पहले शीर्षस्थ स्तर पर हुई समीक्षा बैठकों की झलक टिकट बंटवारे को लेकर साफ दिखाई देती है। समीक्षा के दौरान भीतरघात से बचने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। बात अगर पिछले चुनाव की करें तो पहले व दूसरे चरण की 109 सीटों में से पार्टी ने केवल दो सीट पर जीत दर्ज की थी। जिसमें एक मथुरा की मांट तो दूसरी हापुड़ की धौलाना रही। धौलाना सीट से बसपा से मैदान में उतरे असलम चौधरी ने भाजपा के रमेश चंद्र को तो हराया था। जीत के बाद असलम चौधरी समाजवादी पार्टी में चले गए। बसपा ने इस बार धौलाना से वासिद प्रधान को मौका दिया है। वहीं पार्टी पहले चरण की 27 और दूसरे चरण की 11



2012 से दो प्रत्याशी लगातार इस बार भी मैदान में

वर्ष 2012 के चुनाव में बसपा के खाते में 39 सीटें आई थीं। इनमें 2017 के चुनाव में पार्टी ने 25 सिटिंग एमएल को मैदान में उतारा था। 2017 के चुनाव में कुल दो ही सीटें ही पार्टी के खाते में आई थीं। इनमें दो उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले 2012 फिर 2017 और अब 2022 यानी तीन चुनावों से लगातार बसपा के टिकट पर मैदान में हैं। इनमें रामपुर मनिहारन सीट से रनर रहे रविन्द्र कुमार मोह्लू और गोवर्धन सीट से राजकुमार रावत शामिल हैं। 2012 के चुनाव में ये निर्वाचित हुए थे।

सीटों पर दूसरे नम्बर पर रही। कुल मिलाकर 38 सीटों में से इस बार पार्टी ने धामपुर सीट से पिछली बार लड़े मोहम्मद गाजी को इस बार बिजनौर की बढ़ापुर से मैदान में उतारा है। वहीं सखारनपुर की रामपुर मनिहारन सीट से पिछले चुनाव में रनर रहे रविन्द्र कुमार मोह्लू और मथुरा की गोवर्धन सीट से राजकुमार रावत पर भरोसा जताया है। इसके अलावा सभी सीटों पर नए चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया है।

अभिषेक रंजन | लखनऊ

देश में हो रहे पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव में पूरे देश की नजर यूपी के विधान सभा चुनाव को लेकर है। यहां पर मौजूदा योगी सरकार अपने और केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज के बलबूते विकास और सुशासन की बात को लेकर जनता के बीच जा रही है। वहीं विपक्ष पश्चिम बंगाल की ही तरह खेला होइब्रे की तर्ज पर भाजपा के राष्ट्रवाद के बीच बाजी पलटने की कोशिश कर रहा है। यूपी के चुनाव परिणाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से तो जुड़े हुए हैं ही साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की संभावनाएं का भी दरोमदार 10 मार्च के नतीजों पर टिका है।

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड़ा, सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा मुखिया मायावती के राजनीतिक भविष्य को यह चुनाव परिणाम तय करेगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब दस मार्च के बाद मिल जाएंगे। मसलान क्या अखिलेश यादव विपक्ष के राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व कर पाएंगे? क्या यह मायावती का अंतिम चुनाव होगा? और कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर प्रियंका गांधी वाड़ा को दावेदारी की संभावना बढ़ेगी? यही नहीं यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या विकास के साथ-साथ हिन्दू राष्ट्रवाद की रणनीति अब भी प्रभावी रहेगी?

दरअसल विधान सभा चुनाव की घोषणा होने से पहले पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जनविश्वास यात्राओं के जरिए यूपी को तय दिया था। उन्होंने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की और माफियाओं और अपराधियों पर चलाए गए बुलडोजर का भी खूब जिक्र किया था। अमित शाह ने इन यात्राओं में यूपी विधानसभा 2022 से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 को जोड़ते हुए कहा था कि अगर आप 2024 में पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर देखा चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ को 2022 में उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम बनाना होगा। योगी ने स्वयं को विकास पुरुष



अखिलेश यादव, प्रियंका वाड़ा, मायावती का भी भविष्य तय करेंगे 10 मार्च के परिणाम

और हिन्दू हृदय सम्राट् जैसा चेहरा जनता के बीच साबित करने की कोशिश की है। यदि मोदी-योगी की जोड़ी से बीजेपी की यूपी में सफलता मिलती है तो योगी का कद और अधिक बढ़ जाएगा। योगी आदित्यनाथ को एक बेहतर प्रशासक के तौर पर भी जाना जाता है। अब अगर सपा मुखिया अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यूपी में कोरोना महामारी, किसान आंदोलन, मरगाई व बेरोजगारी जैसे मसले लेकर सत्तारूढ़ दल पर हमलावर हो रहे हैं। वह वर्चुअल चुनाव प्रचार पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने जीत के लिए एक योजना तैयार की है जिसमें रणनीतिक गठबंधन, जीत की संभावनाओं को लेकर उम्मीदवारों को बल, अति पिछड़े वर्गों को लुभाने की कोशिश और आरक्षित सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है। अगर अखिलेश यादव अपनी योजना में कामयाब हो जाते हैं तो विपक्षी पार्टियां उनके साथ आ सकती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी अखिलेश यादव बेहतर तालमेल रखते हैं। इस चुनाव में प्रियंका गांधी वाड़ा ने चुनावी प्रचार की शुरुआत करते हुए उन विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट किया है जहां अन्य पार्टियों का कब्जा है। उनकी नजर खासकर महिला वोटर्स पर है।



पिछड़े नेताओं के जाने से बीजेपी पर क्या पड़ा असर

चुनावों के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान समेत कई विधायक भाजपा से सपा में चले गए। इससे भाजपा में थोड़ा खलबली हुई लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस और सपा के आरपीएन सिंह, आदिति सिंह व अर्पणा जैसे सितारों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जिन नेताओं ने भाजपा छोड़कर सपा में अपनी आस्था दिखाई जनता उन नेताओं को आस्था बसपा से भाजपा और फिर सपा तक का सफर बायबूवी देख और समझ रही है कि किस तरह पूरा कार्यकाल होने के बाद उन्हें पिछड़े और नौजवानों की याद आई। 2019 में भी जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो भी लोग चिंतित हो गए लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो सबसे पहले बसपा मुखिया मायावती ने ही प्रेस काफ्रेंस करके सपा मुखिया अखिलेश को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। बीजेपी भी इस चुनाव में दलित, पिछड़े के साथ सवर्ण का संतुलन बैलेंड हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। उप के पिछले चुनावों में भाजपा का अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदेश में उनकी



जानसंख्या के अनुपात में टिकट दिया था। इस रणनीति में पार्टी कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर रही है। बीजेपी अति पिछड़ी जातियां कुशवाहा, कहार, मल्लाहा, निषाद, लोहार, गडरिया, विश्वकर्मा, बिंद, सैनी, मौर्या आदि को पिछड़ों जातियों कुर्मी, गिरी, गुजर, गोसाईं, लोध, यादव आदि संग संतुलन बना कर पार्टी टिकट बांट रही है। जाहिर है कि टिकट वितरण के इस फार्मुले से बीजेपी को किसी नुकसान की संभावना नहीं दिखती है तब जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं ने भगवा झंडा छोड़ साइकिल की सवारी कर ली है। अब अगर 2014 के लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो 2014 से यूपी में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। यदि 2007 और 2012 विधानसभा चुनावों में 15-16 प्रतिशत वोट पाने वाली भाजपा को 2014, 2017 और 2019 में 40 से 50 प्रतिशत वोट मिल रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि विपक्ष के एकजुट होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी का जादू अभी भी कायम है। केंद्र की मोदी



और योगी सरकार ने अपने काम-काज के जरिए युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, गरीबी रेखा से नीचे वाले, परती-उलेते वाले, वंचित, शोषित समाज के बीच अपनी पैठ बनाई है। बीजेपी के आईटी सेल के एक नेता का कहना है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जीरो बैलेंस पर गरीबों का जनधन खाता खुलवाना शुरू किया था। तब से जनवरी 2022 तक 44 करोड़ जनधन खातों में डेढ़ लाख करोड़ रुपये जमा हैं। यह गरीबों का वह पैसा है जो विभिन्न योजनाओं से सीधे उन्हें अपने खाते में मिला। जिन गरीबों, महिलाओं, कन्याओं, दिव्यांगों, किसानों, विधवाओं, श्रमिकों आदि को पैसे अपने खाते में नियमित मिल रहे हैं। जाहिर है उन्हें जाति नहीं बल्कि वित्तीय सुरक्षा पर ज्यादा भरोसा होगा। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य की सरकार ने योजनाओं का लाभ जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा आदि को देखकर नहीं दिया है। अगर हिन्दू समाज के लोग लाभान्वित हुए हैं तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी लाभ मिला है।

दोबारा सत्ता पाने की दौड़ में डबल इंजन की सरकार कहीं पानी न फेर दे एम फैक्टर

अभिषेक रंजन | लखनऊ

प्रदेश में चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले के माहौल को जर याद करें तो साफ होता है कि यूपी में किस तरह डबल इंजन की सरकार ताबड़-तोड़ विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रही थी। इन कार्यक्रमों की बागडोर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी और उनके साथ मोदी मंत्रिमंडल टीम का हिस्सा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे जो विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। अब जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है और रणभरियों के बीच पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है तो मोदी-योगी सरकार के काम-काज विपक्ष पर तैर बनकर बरसाए जा रहे हैं। पश्चिम से लेकर पूरब तक डबल इंजन सरकार के काम गिनाए जा रहे हैं। इनमें बाबा काशी विश्वनाथ कारीडोर जैसे धार्मिक पर्यटन से लेकर कार्यक्रमों में भी पूर्वी यूपी ही हावी रहा, कुल सात कार्यक्रमों में से उनके पांच कार्यक्रम पूर्वी यूपी में ही हुए। इसमें बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण काफी अहम है क्योंकि यह योजना कई दशकों से अधूरी पड़ी थी। इस परियोजना से नौ जिले लाभान्वित होंगे। यूपी की अहमियत को देखते हुए मोदी बीते दिसंबर महीने में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक ही महीने में दो बार पहुंचे। जाहिर है कि मोदी ने विकास के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर के लगभग हर दिन अलग-अलग जिलों में दौरा किया था। इन जिलों में सीएम योगी के दौरे के साथ ही करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। योगी के इन कार्यक्रमों में धार्मिक महत्व के क्षेत्र, विधानसभा के हिसाब से क्षेत्र और सीटों के गणित का भी भरपूर ध्यान रखा गया। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज में ही लगभग 34 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। योगी ने 20 दिसंबर से आठ जनवरी के बीच लगभग 40 जिलों में कार्यक्रम किए। इन कार्यक्रमों के दौरान सीएम योगी ने 29 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत पर 3000 अलग-अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें, सिंचाई परियोजनाएं,



लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रमों के जरिए पूर्वांचल साधने की भी कोशिश

चुनावी फिजा में विकास का रंग घोलेते हुए मोदी ने सरयू नहर परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया और मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसी योजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में भी पूर्वी यूपी ही हावी रहा, कुल सात कार्यक्रमों में से उनके पांच कार्यक्रम पूर्वी यूपी में ही हुए। इसमें बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण काफी अहम है क्योंकि यह योजना कई दशकों से अधूरी पड़ी थी। इस परियोजना से नौ जिले लाभान्वित होंगे। यूपी की अहमियत को देखते हुए मोदी बीते दिसंबर महीने में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक ही महीने में दो बार पहुंचे। जाहिर है कि मोदी ने विकास के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर के लगभग हर दिन अलग-अलग जिलों में दौरा किया था। इन जिलों में सीएम योगी के दौरे के साथ ही करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। योगी के इन कार्यक्रमों में धार्मिक महत्व के क्षेत्र, विधानसभा के हिसाब से क्षेत्र और सीटों के गणित का भी भरपूर ध्यान रखा गया। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज में ही लगभग 34 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। योगी ने 20 दिसंबर से आठ जनवरी के बीच लगभग 40 जिलों में कार्यक्रम किए। इन कार्यक्रमों के दौरान सीएम योगी ने 29 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत पर 3000 अलग-अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें, सिंचाई परियोजनाएं,

सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सड़क परियोजनाएं, विद्युत विभाग की परियोजनाएं, मेडिकल कॉलेज और कई अन्य तरह की परियोजनाएं शामिल हैं। योगी ने जिन जिलों का दौरा किया है उनमें से ज्यादातर जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। इसे भाजपा की रणनीति भी कहा जा सकता है क्योंकि पश्चिमी यूपी की अपेक्षा पूर्वी यूपी में ब्रैंड योगी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। भाजपा ने न सिर्फ अपनी जीती हुई सीटों पर ध्यान दिया है बल्कि गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेठी-रायबरेली और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में भी तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वह इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अपनी रणनीति के जरिए यूपी को उन हारी हुई विधान सभा सीटों पर फोकस किया है ताकि विकास के जरिए वहां की जनता का दिल जीता जाए। 20 दिसंबर से सात जनवरी के बीच नितिन गडकरी ने यूपी में करीब 13 जिलों में 80 हाइवे का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें भी धार्मिक शहरों को तरजीह दी गई है। मथुरा में 10, इलाहाबाद में चार और अयोध्या में छह राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है। गडकरी ने लगभग 69539 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनने वाले कुल 80 हाइवे और उनसे जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस काफ्रेंस से पहले योगी आदित्यनाथ ने आठ जनवरी को लखनऊ के पीजीआई में 600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था।

में पूर्वांचल एक्सप्रेसव का लोकार्पण, शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण और अयोध्या में गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण जैसी तमाम कार्यक्रम

शामिल हैं। मोदी-योगी सरकार ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी कोशिशों से सीधा संवाद और संगत दोनों ही इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं कि डबल इंजन की

मोदी-योगी सरकार की प्रमुख योजनाएं

मोदी सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं में प्रधान मंत्री जन-धन योजना, जन-धन से जन सुरक्षा, प्रधानमंत्री प्रधान ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श गांव योजना, सत्यमेव जयते योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हृदय योजना, उजाला योजना, अटल पेंशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्वर्ण मौद्रिकरण योजना, स्वर्ण बांड योजना, उदय योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप इंडिया, ग्रामोदय से भारत उदय, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, नमामि गंगे योजना है। योगी सरकार की प्रमुख योजनाओं में उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, प्रो टेबलेट, स्मार्ट फोन योजना, यूपी स्कॉलरशिप योजना, उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, बीसी सखी योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यूपी प्रो बोरिंग योजना, वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट योजना, यूपी मिशन शक्ति अभियान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल प्रमुख हैं।

सरकार से कितने लोग लाभान्वित हुए। इन कार्यक्रमों में केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन योजना, यूपी की लैपटॉप, टैबलेट वितरण योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री शहरी-ग्रामीण आवास योजना समेत उन कई योजनाओं को शामिल नहीं किया गया है जिनमें व्यक्तियों या परिवारों को सीधे तौर पर फायदे दिए जा रहे हैं।



कहीं त्रिकोणीय तो कहीं आमने-सामने की लड़ाई

सतीश सिंह | लखनऊ

किसान आंदोलन के बाद जहां समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को इस बार विधानसभा चुनाव में जाट-मुस्लिम मतदाताओं के साथ आने की उम्मीद है, वहीं पश्चिमी यूपी में कई सीटें ऐसी हैं जहां एम फैक्टर को लेकर विपक्ष त्रिकोणीय लड़ाई की भूमिका में नजर आ रहा है। एम फैक्टर पर भरोसा जहां गठबंधन ने जताया है वहीं बसपा ने बीडीएम समीकरण को ध्यान में रखते हुए एम फैक्टर को आगे रखा है। वहीं पिछले दो चुनावों से पश्चिमी यूपी में जगह बनाने की कोशिश कर रहे एमआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी भी इसी फैक्टर के सहारे नवदेव अयाज हैं तो सपा से महबूब अली हैं। मेरठ डिस्ट्रिक्ट से बसपा से कुंवर दिलशाद अली हैं तो सपा से मो.आदिल हैं। कोल सीट से बसपा से मो बिलाल हैं तो सपा से शाज इसहाक हैं। अलीगढ़ सीट से बसपा से रजिया खान हैं तो सपा से जफर आलम मैदान में लड़ रहे हैं। इन सभी में तसलीम अहमद, नवाबजान, महबूब अली सिटिंग कैंडिडेट हैं।

इन सीटों पर एम फैक्टर को लेकर बसपा और गठबंधन आमने-सामने

इस चुनाव में बसपा जहां बीडीएम समीकरण पर चल रही है तो वहीं गठबंधन में सपा को यकीन है कि एम फैक्टर उसके साथ है। ऐसे में कई सीटें ऐसी हैं जहां एम फैक्टर की आमने सामने टक्कर है। इनमें नजीबाबाद सीट से जहां बसपा ने शाहनवाज आलम को टिकट दिया है वहीं सपा ने तस्लीम अहमद को मैदान में उतारा है। इसी तरह ठाकुरद्वारा से बसपा के टिकट पर मुजाहिद अली हैं तो सपा के टिकट पर नवाबजान लड़ रहे हैं। चमरौज्या से बसपा से अब्दुल मुस्तफ हुसैन हैं तो सपा से नसीर अहमद खान लड़ रहे हैं। अमरौरा में बसपा से मो. नावेद अयाज हैं तो सपा से महबूब अली हैं। मेरठ डिस्ट्रिक्ट से बसपा से कुंवर दिलशाद अली हैं तो सपा से मो.आदिल हैं। कोल सीट से बसपा से मो बिलाल हैं तो सपा से शाज इसहाक हैं। अलीगढ़ सीट से बसपा से रजिया खान हैं तो सपा से जफर आलम मैदान में लड़ रहे हैं। इन सभी में तसलीम अहमद, नवाबजान, महबूब अली सिटिंग कैंडिडेट हैं।

यहां बसपा और एमआईएमआईएम के बीच टक्कर

एम फैक्टर के सहारे पश्चिमी यूपी में जगह बनाने की जुगत में लगे ओवैसी और बसपा के बीच मुस्लिम वोटों की लेकर कई सीटों पर टक्कर हो रही है। इनमें मुरादाबाद देहात से बसपा ने अकील चौधरी को मैदान में उतारा है तो एमआईएमआईएम ने मो. फ़ख़ानी को टिकट दिया है। इसी तरह मुरादाबाद नगर से बसपा के इरशाद हुसैन सैफ़ी हैं तो ओवैसी की पार्टी ने वाकी राशिद को मैदान में उतारा है। नकुड़ से बसपा के टिकट पर साहित खान लड़ रहे हैं तो एमआईएमआईएम ने रिजवाना को टिकट दिया है। कुंदरकी सीट से बसपा के टिकट पर जहां मोहम्मद रिजवान लड़ रहे हैं तो वही ओवैसी ने हाफिज वारिस पर भरोसा जताया है। लोनी सीट से बसपा के टिकट पर हाजी अकील चौधरी मैदान में हैं तो ओवैसी ने डॉक्टर महाताब को मैदान में उतारा है। बसपा से वासिद प्रधान हैं तो गठबंधन ने असलम अली को मैदान में उतारा है। यहां से ओवैसी की पार्टी ने हाजी आरिफ को टिकट दिया है। सिवालखस सीट से बसपा ने मुकर्रम अली को टिकट दिया है तो गठबंधन से उमर अली खान भाग्य आजमा रहे हैं। इसी सीट पर एमआईएमआईएम से अमजद अली मैदान में हैं। इसी तरह धौलाना सीट पर

सतीश सिंह | लखनऊ

